JustJobs NETWORK

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

EXECUTIVE SUMMARY

फरवरी 2020

भारत तथा इंडोनेशिया में युवा रोज़गार के परिणामों को आकार देने में छोटे शहरों की भूमिका

Mukta Naik & Gregory Randolph

कार्यकारी सारांश

पूरी दुनिया में कई उभरती हुयी अर्थव्यवस्थायें अपने आप को "जनसांख्यिकीय लाभांश" नाम की महत्वपूर्ण स्थिति में पा रही हैं । इस स्थिति में कामकाजी वर्ग के वयस्कों की संख्या का बच्चों और बड़ों की संख्या के साथ अनुपात लगातार ऊंचाई पर जा रहा है । अगर युवा वर्ग के लिए उत्पादक काम के अवसर पैदा कर इस स्थिति को बल प्रदान किया जाए तो इस अनुकूल जनसांख्यिकीय के जरिये अधिक समृद्धि लाई जा सकती है ।

हालांकि जनसांख्यिकीय लाभांश को मापने, इसका अनुमान लगाने और इसकी क्षमता को वास्तविक रूप प्रदान करने को लेकर काफी अध्ययन हुए हैं, लेकिन इस नीतिगत चुनौती के एक आवश्यक पहलू पर बहुत कम ध्यान दिया गया है । और वह जनसांख्यिकीय लाभांश के 'कहां' से जुड़ा हुआ है । युवा वर्ग काम की तलाश में कहां जा रहे हैं? उनकी आर्थिक क्षमताओं की पूर्ति कहां हो सकती है? आर्थिक प्रगति की आशा में यह युवा वर्ग ज्यादा अवसरों की तलाश में कहां जाता है?

यह रिपोर्ट बताती है कि जनसांख्यिकीय लाभांश असल में उन जगहों पर है, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है: विभिन्न तरह के गैर-महानगरीय शहरी क्षेत्र । छोटे शहर, द्वितीयक और तृतीयक शहर, ऐसी ग्रामीण आबादियां जिनमें शहरी विशेषताएं हैं और ऐसी जगहें जहां शहरी रूपांतरण हो रहा है- इस रिपोर्ट में इन सभी जगहों को 'छोटे शहर' कहा गया है। ये ही वे जगहें हैं जहां जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़े अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। इस रिपोर्ट में छोटे शहरों को विस्तार से समझा गया है- इन शहरों में मौजूद रोजगार के अवसरों, इनमें होने वाले प्रवास के रुझानों और शहरी शासन से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए दुनिया के दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत और इंडोनेशिया का उदाहरण लिया गया है।

हमारा मानना है कि छोटे शहर जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए तीन वजहों से महत्वपूर्ण हैं:

1. छोटे शहरों में गैर-कृषि रोजगार पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है।

भारत में गैर-कृषि कार्यों में लगे प्रति 4 युवाओं में से 1 युवा गैर-महानगरीय शहरी क्षेत्र में निवास करता/करती है । इंडोनेशिया में यह अनुपात और भी ज्यादा है: गैर-कृषि युवा रोजगार का 38.5 फीसदी हिस्सा गैर-महानगरीय शहरी आबादियों में है। ये जगहें भी तेजी से बढ़ रही हैं । इंडोनेशिया में भविष्य में होने वाले शहरी विकास का 85 फीसदी ऐसे शहरी क्षेत्रों में होने का अनुमान है जिनकी जनसंख्या साल 2010 में 750,000 से कम थी । हालांकि भारत में 2001-2011 के बीच दस लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर 6.7 फीसदी की दर से बढ़े हैं, बावजूद इसके सेन्सस टाउंस यानी कि वे जगहें जो पुर्नवर्गीकरण के बाद शहर बन गयी हैं, भी 6.4 फीसदी की दर से बढ़ी हैं।

---

1. इस रिपोर्ट के लिये हमनें भारत में गैर-मेट्रोपोलिटन शहरों को 10 लाख से कम निवासियों वाली आबादियों के रूप में वर्गीकृत किया है। इंडोनेशिया में गैर-मेट्रोपोलिटन शहर इंडोनेशिया के 9 बड़े मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्र हैं। यह विश्व बैंक द्वारा साल 2012 में तैयार रिपोर्ट में लिखी परिभाषा के अनुरूप है। (एलीस, पी। 2012) The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development in Indonesia | Jakarta: World Bank | Retrieved from: http://www|worldbank|org/en/news/feature/2012/08/13/towards-inclusive-and-sustainable-regional-development)

2. छोटे शहर ग्रामीण-शहरी प्रवास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

इंडोनेशिया में, साल 2010 से 2015 के बीच एक युवा व्यक्ति (15-29 आयु वर्ग) के किसी महानगरीय क्षेत्र के शहरी केंद्र में आने के बजाय उसे छोड़ने की संभावना थी । यहां तक कि महानगरीय क्षेत्रों के किनारों पर स्थित शहरी क्षेत्रों में युवाओं में आने और जाने की प्रवास दर लगभग समान रही है । इसके विपरीत इंडोनेशिया के छोटे शहर ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होने वाले प्रवास के चलते लगातार बढ़ रहे हैं । साल 2010-15 के बीच केवल प्रवास से इन शहरों की युवा जनसंख्या औसतन 3 फीसदी की दर से बढ़ी है । भारत में कुल 24.6 फीसदी प्रवासी युवा गैर-महानगरीय शहरों में जाते हैं जबकि महानगरीय शहरों में जाने वाले युवाओं की दर महज 12 फीसदी है, जहां प्रवास की दर लगातार गिर रही है।

3. इन-सीटू ग्रामीण से शहरी रूपांतरण के चलते छोटे शहरों का लगातार प्रसार हो रहा है।

बहुत से ग्रामीण युवा ऐसी आबादियों में रह रहे हैं जो जनसांख्यिकीय वृद्धि, सघनीकरण और गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों में हो रहे संक्रमण के चलते धीरे-धीरे शहरी बन रहे हैं । ये कस्बे भारत और इंडोनेशिया के गैर-महानगरीय शहरों का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । इसके चलते ये शहर उत्पादक कार्यों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक विकास और संरचनागत रूपांतरण की प्रक्रियाओं की बढ़ती महत्ता के चलते, यह रिपोर्ट भारत और इंडोनेशिया में छोटे शहरों को चार आपस में सम्बंधित विषयों के तहत समझती है:

• **श्रम बाजार संक्रमण:** जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिये बड़े पैमाने पर उद्योगों और सेवाओं में रोजगार की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया छोटे शहरों में बड़ी नीतिगत चुनौतियां पेश करती है। युवा लोगों को न सिर्फ नए तकनीकी स्किल्स हासिल करनी चाहिये बल्कि नयी सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी चाहिये। इसके अलावा, कृषि कार्यों से गैर-कृषि कार्यों के संक्रमण को आसान बनाने के अलावा नीतिगत ढांचों को रोजगार के नये रास्ते भी तैयार करने चाहिए ताकि उन्हें वास्तविक और टिकाऊ आर्थिक प्रगति का अनुभव हो सके।

• **प्रवास से जुड़ी चुनौतियां:** युवा प्रवासियों को उत्पादक रोजगार अवसर मुहैया कराने के अलावा, छोटे शहर उच्च स्तर के प्रवास से जुड़ी व्यापक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। इनमें से कुछ चुनौतियां परंपरागत शहरी नियमन से जुड़े मुद्दे हैं: आवास, पानी, साफ़-सफाई और यातायात। बाकी चुनौतियां प्रवास से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं से जुड़ी हैं। छोटे शहरों में आए नए प्रवासियों को किस तरह शहर से जुड़ने के लिए मदद मिल सकती है? कैसे इन नए प्रवासियों में काम और सामाजिक स्तर अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद की जा सकती है?

• **लैंगिक मुद्दे (जेंडर):** भारत और इंडोनेशिया में महिलाओं के लिए काम के असमान अवसरों के चलते छोटे शहरों के मुद्दों को कामकाजी महिलाओं के नजरिए से देखना जरूरी है- भारत और इंडोनेशिया के गैर-महानगरीय शहरों में हो रहे संरचनागत रूपांतरण किस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं? पितृसत्ता काम के अवसरों को भी सीमित करती है- किस प्रकार की नीतियां और संस्थायें महिलाओं को इन सीमाओं को पार करने में मदद कर सकती हैं?

• **शहरी शासन:** तेज विकास और रूपांतरण के चलते छोटे शहरों में शासन से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं । इनमें शामिल है: जो जगहें न तो पूरी तरह ग्रामीण हैं और न ही शहरी, उनके शासन के लिए सही प्रशासनिक संरचनाएं क्या होनी चाहिए ? छोटे शहरी इलाकों, जहां लगभग पूरी अर्थव्यवस्था असंगठित है, वहां लोगों और अधिसंरचनाओं से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण निवेश के लिये स्थानीय आमदनी कैसे उत्पन्न हो सकती है? किस तरह ग्रामीण और शहरी इलाकों के परस्पर संबंधों को समझकर छोटे कस्बों और गावों दोनों का ही फायदा हो सकता है?

केस सिटी दृष्टिकोण

द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण के अलावा, इस अध्ययन में किया गया शोध केस अध्ययन विधि पर आधारित है। इसके लिए दो देशों के भीतर चार शहरों का चयन किया गया है। इन शहरों का चयन भारत और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय शहरीकरण रुझानों, भूगोल और श्रम बाजार की विविधता का ध्यान रखकर किया गया हैं। इन चार जगहों में से प्रत्येक जगह पर शोध टीम ने कामकाजी युवाओं के साथ 500 सर्वेक्षण, 10-15 फोकस ग्रुप डिस्कशन किये. साथ-साथ सरकार, निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसायटी संस्थानों के 20-30 स्थानीय प्रतिनिधियों के इंटरव्यू किये।

• **किशनगढ़, राजस्थान [भारत]:** राजस्थान के अजमेर जिले में 154,000 आबादी वाला शहर किशनगढ़ मार्बल प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और व्यापार का केंद्र है। इस संगमरमर उद्योग के चलते आस-पास के निर्धन ग्रामीण इलाकों से ग्रामीण-शहरी आबादी किशनगढ़ में आती है, इसके अलावा ग्रामीण-शहरी प्रवास को भी बल मिलता है। हाल में शुरू हुई अधिसंरचना परियोजनाओं के कारण शहर का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। इन परियोजनाओं में थोक चने का बाजार, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर और नया हवाई अड्डा शामिल है।

• **मंगलौर, कर्नाटक [भारत]:** भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित दक्षिणी राज्य कर्नाटक में 498, 000 आबादी वाला मंगलौर दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रशासनिक और वित्तीय मुख्यालय है। अगर भौगोलिक नजरिये से देखें तो यह शहर दक्षिणी राज्य केरल से लेकर गोवा तक फैले हुए स्थापित प्रवासी नेटवर्कों में एक मुख्य जगह है । साथ-साथ धार्मिक समूहों के मिश्रण और भाषाई विविधता के लिहाज से यह शहर भारत के छोटे शहरों में सबसे अधिक विविधतापूर्ण शहर है। यहां रोजगार मुख्य रूप से कृषि-प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), पेट्रो-कैमिकल विनिर्माण और उभरते हुए सेवा क्षेत्र में है।

• **कुपांग, पूर्वी नुसा तेंग्गारा [इंडोनेशिया]:** कुपांग इंडोनेशिया के सबसे कम विकसित क्षेत्रों और द्वीपसमूह के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित है. यह पूर्वी नुसा तेंग्गारा राज्य से घिरा हुआ अपेक्षाकृत समृद्ध द्वीप है। यह प्रांतीय राजधानी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी युवाओं के लिए अवसरों का उभरता हुआ केंद्र है । राज्य-समर्थित विकास कार्यों और उसके बाद विकेंद्रीकरण से जुड़े सुधारों के बाद इस जगह का विकास तेजी से हुआ है। शिक्षा और अधिसंरचना में हो रहे निवेश के चलते युवा इस जगह को लगातार सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्रदान करने वाले शहरी केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हालांकि यहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक राज्य द्वारा किए जा रहे खर्च और उपभोग पर निर्भर करती है।

• **सेमारंग रेजेन्सी, सेन्ट्रल जावा [इंडोनेशिया]:** इस प्रोजेक्ट के लिए केस अध्ययनों के रूप में चुनी गयी चार जगहों में से एक सेमारंग रेजेन्सी एक

2. किशनगढ़ के छोटे आकार के चलते, शहर के केवल 400 कामकाजी युवाओं के साथ सर्वेक्षण किया गया है।

मात्र जगह है जिसे आधिकारिक तौर पर शहर होने की मान्यता नहीं मिली है । यह रेजेन्सी केन्द्रीय जावा के उस क्षेत्र का हिस्सा है जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और जहां ग्रामीण तथा शहरी आर्थिक गतिविधियों का मिश्रण और भूमि उपयोग की विविधता है। यह सभी बातें इस रेजेन्सी को देसकोता क्षेत्र का उदहारण बनाती हैं। हालांकि इस रेजेन्सी में सिंगापुर से 35 फीसदी अधिक बड़े भूमि क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोग रहते है, लेकिन इसकी शहरी जनसंख्या 400,000 है जो एक घने हाइवे कारिडोर के आस-पास बसी है। विनिर्माण (जिसमें श्रम की ज्यादाआवश्यकता हो) की तीव्र बढ़ोत्तरी की वजह से इस जगह का पिछले दो दशकों में शहरीकरण और विस्तार हुआ है।

मुख्य निष्कर्ष

यह रिपोर्ट भारत और इंडोनेशिया में छोटे शहरों के रूपांतरण विषय पर तीन सालों तक किये गए शोध कार्य पर आधारित है। शोध के निष्कर्षों को पांच विषयगत समूहों में पेश किया गया है- इनमें से प्रत्येक समूह के लिये प्राथमिक और द्वितीयक जानकारियों का इस्तेमाल किया गया है। साथ-साथ इस प्रोजेक्ट के तहत विश्लेषित किये गये चार शहरों से बहुतायत जमीनी उदाहरणों का इस्तेमाल भी इस शोध के लिये किया गया है।

विषय 1- बहु प्रवासीय मार्गों के चौराहे पर

प्रवास जंक्शन

छोटे शहर कई अर्थों में प्रवास जंक्शनों की तरह काम करते हैं। एक ग्रामीण युवा व्यक्ति एक छोटे शहर में प्रवास कर सकता है और वहां आवश्यक स्किल हासिल कर किसी अन्य स्थान पर रोजगार के लिये जा सकता है। इसको स्टेप-माइग्रेशन (Step-migration) भी कहा जाता है। या वह काम के लिये किसी छोटे शहर जा सकता है और उसके बाद वह अपने मूल स्थान पर लौट सकता है। एक छोटे शहर में युवा लोग बेहतर अवसरों की तलाश में कहीं अन्य महानगरों में भी जा सकते हैं। और इस तरह प्रवासियों का अन्य समूह उस जगह में श्रमबल में आयी कमी की भरपाई करता है। छोटे शहरों में इस तरह देखे गए प्रवास के बहु मार्ग भारत और इंडोनेशिया के जटिल प्रवास परिदृश्य पर रोशनी डालते हैं।

स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रवास मार्गों में विविधता

हमारे चयनित शहरों में प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और इस मानक पर इन शहरों में काफी भिन्नता दिखायी देती है। जहां इंडोनेशिया के शहरों में एक ही राज्य, खासकर पड़ोसी शहरों और रेजेंसियों से प्रवासी आते हैं, वहीं हम देखते हैं कि भारतीय शहरों में आस-पास और दूर-दराज दोनों जगहों से आंतरिक प्रवास होता है।

छोटे शहरों के प्रवास मार्गों में आर्थिक भौगोलिकताओं की झलक मिलती है

जहां एक तरफ भारत में आबादी का बड़ा हिस्सा न्यूनतम विकसित राज्यों में रहता है, वहीं इंडोनेशिया में ये स्थिति ठीक विपरीत है। जनसंख्या संकेंद्रता और आर्थिक विकास के बीच के इस परस्पर विरोधाभासी संबंध के चलते विभिन्न प्रवास मार्ग देखे जाते है। उत्तर और पूर्वी राज्यों के अपेक्षाकृत निर्धन राज्यों में बाहरी प्रवास बहुत ज्यादा होता है। इन राज्यों के प्रवासी किशनगढ़ और मंगलौर जैसे छोटे शहरों समेत देश भर के छोटे और बड़े शहरों में पाये जाते हैं। इसके विपरीत इंडोनेशिया के न्यूनतम

3. देसाकोत शब्द टेरी मैकगी का दिया हुआ है। यह उन क्षेत्रों के लिये इस्तेमाल होता है जहां उच्च जनसंख्या घनत्व, गहन कृषि उपयोग, विकसित यातायात नेटवर्क, उच्च जनसंख्या गतिशीलता, कृषि क्षेत्र से बाहर बढ़ती गतिविधियों और भूमि उपयोग के विभिन्न रूपों के बीच सह-अस्तित्व होता है।

विकसित राज्यों से बाहर जाने वाले प्रवासियों की कुल संख्या जावा जैसे छोटे शहरों के शहरी श्रम बल में हिस्सेदारी के लिहाज से बहुत कम है। जावा इंडोनेशिया का सबसे अधिक आबादी वाले और औद्योगीकृत द्वीप है।

आना-जाना और वापसी प्रवास

अध्ययन के लिये चयनित चार में से तीन शहरों (कुपांग के अलावा) में हमनें पाया कि छोटे शहरों के दायरों में रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी आजीविका के लिये रोजाना शहर में आते-जाते हैं। यातायात के आधारभूत ढांचे में हुये सुधार और दुपहिया वाहनों के लिए मिलने वाले कर्ज ने इसे और आसान बनाया है। यहां तक कि जिन छोटे शहरों में प्रवासी काम के साथ-साथ रहते भी हैं, वहां पर भी बहुत से प्रवासियों के अपने मूल समुदायों से मजबूत रिश्ते बने रहते हैं और वे वापस जाने की सोचते हैं। ये बात वहां ख़ास तौर पर देखी जा सकती है, जहां औद्योगिक रोजगार में बहुत तेज बढ़ोत्तरी हुयी है। जैसे कि किशनगढ़ और सेमारंग रेजेन्सी, चूंकि इन नौकरियों से दीर्घकालिक आर्थिक अवसर नहीं मिले हैं।

विषय 2- छोटे शहरों की उभरती हुयी अर्थव्यवस्थायें: विशेषीकृत या विविध? लचीली या असुरक्षित?

विशेषीकृत अर्थव्यवस्थायें, विविध श्रम बाजार

हमारे द्वारा चयनित शहरों का अध्ययन दिखाता है कि छोटे शहरों में उपलब्ध रोजगार अवसरों में भी बहुत विभिन्नता है। यह भिन्नता किशनगढ़ और सेमारंग जैसे शहरों में भी दिखायी पड़ती है जहां अर्थव्यवस्थाएं ठोस रूप से मार्बल प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और कपड़ा विनिर्माण जैसे विशेष क्षेत्रों पर निर्भर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, सेमारंग रेजेन्सी में फैक्ट्री कामगारों की बड़ी संख्या के चलते बहुत से अन्य सामानों और उत्पादों के लिए मांग पैदा हुयी है। बड़ी फैक्ट्रियों के इर्द-गिर्द कई असंगठित आर्थिक गतिविधियां पैदा हुयी हैं – जैसे कि छोटे उपक्रम जो हाउसिंग (कोस्त), लांड्री सेवायें, फास्ट फ़ूड (वारुंग), सुरक्षित पार्किंग सेवायें और मोटरबाइक रिपेयर आदि सेवायें देते हैं।

"फुटलूज" और "स्टिकी" क्षेत्र

छोटे शहरों की कम लागत वाले क्षेत्रों (लोअर वैल्यू एडेड सेक्टर्स) में विशेषज्ञता होती है, जहां ज्यादातर कामगारों के पास बुनियादी शिक्षा होती है और उन्हें सीमित उपयोगिता वाले रोजमर्रा के कामकाज करने होते हैं। किशनगढ़ में लिये गये हमारे युवाओं के सैम्पल में केवल 6.8 फीसदी और सेमारंग रेजेन्सी में केवल 1.8 फीसदी युवाओं के पास यूनिवर्सिटी डिग्री है। छोटे शहरों की विशेषीकृत अर्थव्यवस्थाओं के लिये इस बात के महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते थे। व्यापार करने योग्य कम लागत वाले क्षेत्र अक्सर इन मायनों में "फूटलूज" होते हैं कि उन्हें कई जगहों से संचालित किया जा सकता है। इसके विपरीत "स्टिकी" क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो ख़ास स्थानीय परिस्थितियों जैसे बेहद कुशल कामगारों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा कम लागत वाले क्षेत्रों में रोजमर्रा के कार्य के चलते ऑटोमेशन का खतरा है। अगर इन क्षेत्रों को स्थानीय लाभ नहीं मिल पाते तो छोटे शहरों की अर्थव्यवस्थाओं पर दीर्घकालिक संरचनागत चुनौतियों का प्रभाव पड़ सकता है।

स्थानीय संपत्ति, स्थानीय पूंजी

जहाँ छोटे शहरों की अर्थव्यवस्थाएं स्थानीय संपत्तियों और स्थानीय तथा विदेशी दोनों तरह की पूंजियों के के आधार पर विकसित होती हैं, वहां ऑटोमेशन जैसे खतरे कम पाए जा सकते हैं। मार्बल प्रसंस्करण

(प्रोसेसिंग) उद्योग में गुणवत्ता से जुड़े कुछ मुद्दों के बावजूद किशनगढ़ इस बात का अच्छा उदाहरण है। मार्बल प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) केंद्र के रूप में इसका विकास मुख्य तौर पर राजस्थान के स्थानीय निवेशकों से संभव हुआ है। साथ-साथ उद्योग के विकास और विस्तार के प्रति स्थानीय फर्मों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नजर आती है । इस बात के शुरुआती तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले मार्बल की आपूर्ति जल्द ही खत्म हो जायेगी: इसी का नतीजा है कि किशनगढ़ की मार्बल प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) फैक्ट्रियों ने राजस्थान के बाहर और यहां तक कि भारत के बाहर से भी कच्चे माल की आपूर्ति शुरू कर दी है।

विषय 3- अवरुद्ध आर्थिक प्रगति: छोटे शहरों के रोजगार परिदृश्य के अंर्तविरोध

आर्थिक पायदान पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना

छोटे शहर विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाते हैं। अधिकांश मामलों में ये ऐसी प्रगति होती हैं जिनसे आर्थिक तौर पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है। गुजर-बसर के लिये कृषि पर निर्भर परिवारों से आने वाले निर्धनतम प्रवासी, मजदूरी आदि कार्यों (या जैसा कि बहुत से लोग बताते हैं) और पैसे की तलाश में छोटे शहरों में आते हैं। जिनके पास बुनियादी शिक्षा है और जो ऐसे परिवारों से आते हैं जो बेहद गरीबी का सामना नहीं कर रहे हैं, को सामान्यतः छोटे शहरों की संगठित कंपनियों में नियमित काम के अवसर मिल जाते हैं। ये कंपनियां, जैसे कि सेमारंग कपड़ा विनिर्माण समूह न्यूनतम मजदूरी देती है। आखिरकार, युवा वर्ग का बेहद छोटा सा हिस्सा ही इन छोटे शहरों में हुनरमंद उद्यमियों या व्यवसायिक और सरकारी सेवाओं में काम के माध्यम से भारत और इंडोनेशिया के मध्य वर्ग की श्रेणी में शामिल हो पाता है। इन रोजगार अवसरों के अलावा, ये छोटे शहर शिक्षा के अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं को भी आकर्षित करते हैं। कुपांग में एक तिहाई प्रवासियों ने सर्वेक्षण में शिक्षा को प्रवास का मुख्य कारण बताया।

फंस जाना: आर्थिक प्रगति की चुनौतियां

मजदूरी, संगठित अर्थव्यवस्था से जुड़ी नौकरियों, उद्यमिता और शिक्षा के रूप में युवाओं को मिलने वाले अवसरों के बावजूद शोध के लिए चयनित हमारे शहर दिखाते हैं कि ये सभी अवसर सीमित हैं। छोटे शहरों में काम करने वाले युवा मुख्य रूप से नौकरियों के खत्म होने की संभावना के बारे में चिंतित रहते हैं। इन नौकरियों में प्रगति के अवसर बहुत कम होते हैं, खासकर से उन छोटे शहरों में जहां अर्थव्यवस्थायें उद्योगों के इर्द-गिर्द विकसित हुयी हैं।

बहुत से छोटे शहरों के श्रम बाजारों में शिक्षा पर सीमित रिटर्न भी इससे जुड़ा एक मुद्दा है। किशनगढ़ और सेमारंग रेजेन्सी के औद्योगिक क्षेत्रों ने श्रम बाजार को शिथिल सा कर दिया है। यहां की फैक्ट्रियां बड़ी संख्या में निचले और मध्यम स्तर की शिक्षा वाले युवाओं को काम पर रखती हैं। इन फैक्ट्रियों में वेतन का वितरण काफी संकरा है। कुपांग और मंगलौर जैसी अपेक्षाकृत विविध और सेवान्मुख अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरी के वितरण में काफी अंतर है। हालांकि रोजगार कम लागत और कम भुगतान वाले सेवा क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रित है। जहां एक तरफ महानगरीय अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी संख्या में व्यवसायिक नौकरियां मिलती हैं वहीं छोटे शहर की अर्थव्यवस्थायें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुणवत्तापूर्ण नौकरियां देने के लये संघर्ष करती नजर आती हैं। कुपांग में, उच्च स्तर की शिक्षा पाये हुये युवाओं की आमदनी में वृद्धि धीमे होती है।

आखिरकार, बहुत से युवाओं को आर्थिक प्रगति के लिये अस्थिर काम की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। किशनगढ़ में हमारे सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 2 फीसदी से भी कम कामगारों के पास लिखित कांट्रेक्ट था। इसके साथ-साथ 37.3 फीसदी कामगार प्रति दिन औसतन 10 या उससे अधिक घंटों तक काम करते हैं। सेमारंग रेजेन्सी में काम करने वाले आधे से अधिक कामगारों ने सर्वेक्षण में बताया कि कार्यस्थलों पर वे खतरों से घिरे रहते हैं। इनमें भी 46.6 फीसदी ने बताया कि उन्हें काम पर चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुयी है। इस प्रकार के मुद्दे विभिन्न शहरों में अलग-अलग है। जो श्रम बाजार अधिक असंगठित हैं, वहां दिहाड़ी मजदूरों को अनिश्चित काम के घंटों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने ऐसी स्थितियों के बारे में बताया जब काम नहीं मिलने पर उन्हें दिन का खाना छोड़ना पड़ा।

विषय 4- छोटे शहरों में महिलाओं के लिए 'नेगोशिएटेड' अवसर

काम में महिलाओं की भागीदारी और विवाह-प्रवास

छोटे शहरों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य, श्रम और विशेषकर निर्यात-उन्मुख उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी के व्यापक रुझानों को दिखलाते हैं। महिला प्रवासियों को छोटे शहरों द्वारा मुहैया कराये जाने वाले अवसरों में परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी होता है। इंडोनेशिया में यह भाव सेमारंग रेजेन्सी में 'फैक्ट्री डॉटर' के रुझान में दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसा ही अनुभव कुपांग का भी हैं जहां महिलाओं को उनके रिश्तेदारों के पास काम करने के लिये भेज दिया जाता है। भारत में विवाह-प्रवास की परिघटना-जहां महिलायें शादी के बाद अपने पति के घर जाकर रहती हैं-भी महिला कामगारों को शहरी श्रम बाजारों में ले आती है, जहां आंकड़ों के स्तर पर वे अपने गैर-प्रवासी साथियों की तुलना में अधिक काम करती हैं।

"महिलाओं के काम" के परे देखना

हमारे चयनित शहरों में महिलाओं के रोजगार मुख्यतः "महिलाओं के काम" की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे काम होते हैं जिन्हें समाज महिलाओं के लिए स्वाभाविक रूप से करने योग्य मानता है। इन कार्यों में सेमारंग रेजेन्सी के कपड़ा क्षेत्र में काम करना (जहां 'उंगलियों को फुर्ती से चलाना' होता है), मंगलौर में नर्सिंग कार्य में देखभाल और साफ़-सफाई करना, किशनगढ़ में घर पर क्राफ्ट और टेलरिंग का काम आदि शामिल है। हालांकि सेवा क्षेत्र के विस्तार ने कुपांग में रिटेल और मंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी जैसे लैंगिक आधार पर कम बंटे हुए क्षेत्रों में काम के नये अवसर पैदा किये हैं। यह रुझान संकेत करता है कि छोटे शहरों में महिलाओं को श्रम बाजार की परंपरागत भूमिकाओं से अलग कर सक्षम बनाने की संभावनायें होती हैं।

छोटे शहरों के श्रम बाजारों में महिलाओं के लिये बाधायें और मजबूतियां

हालांकि महिलाओं की तुलना में छोटे शहरों में अधिकांश पुरुष असुरक्षित नौकरियां करते हैं, बावजूद इसके महिलओं को पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं के चलते विशेष तरह की असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कुपांग में यह बेहद आम है कि नियोक्ता द्वारा महिला कर्मचारियों को खाने और रहने की जगह दी जाये, साथ-साथ उन पर आने-जाने की पाबंदियां लगायी जाएं ,और उनसे लम्बे समय तक काम करने की उम्मीद की जाये, बिना अतिरिक्त मुआवजे के। मंगलौर में महिला घरेलू कर्मचारियों ने अपने घर के भीतर सीमित

वित्तीय स्वायत्तता की बात बतायी। सेमारंग रेजेन्सी के कपड़ा उद्योग में बनाये गए कपड़ो की संख्या के आधार पर मजदूरी मिलती हैं, जिसके चलते काम के घंटे बढ़ जाते हैं और आमदनी की क्षमता भी घट जाती है। इसके अलावा, हमारे चयनित शहरों में महिलाओं की संख्या ऐसे रोजमर्रा के कामों में अधिक है जो वे पूरी उम्र नहीं कर सकती। साथ-साथ ऐसे कामों के ऑटोमेशन का खतरा भी है।

प्रवासी महिलाओं पर तीन तरफ से बोझ पड़ता है। उदाहरण के लिये, प्रवासी होने के अनुभवों के परे, सेमारंग रेजेन्सी में महिलाओं को एक ही तरह का काम बार-बार दोहराना पड़ता है और उनके कौशल विकासके लिए सीमित अवसर हैं। इसके साथ-साथ उन्हें देखभाल करने और घर में पैसा भेजने, दोनों के रूप में परिवार के प्रति भी ठोस जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। किशनगढ़ में "विवाहित महिला प्रवासियों" को आने-जाने से जुड़ी पाबंदियों और महिलाओं के काम करने से जुड़े सामाजिक कलंकों से जूझना पड़ता है। इस तरह छोटे शहर महिलाओं को काम के अवसर भारी कीमत पर मुहैया कराते हैं।

स्टार्ट-अप पूंजी का अभाव महिला उद्यमिता के अवसरों को सीमित करता है। करियर के प्रति दिशा के अभाव में बहुत सी महिलायें बिना भुगतान के पारिवारिक काम करने लगती हैं, गर्भवती होने पर या उद्योगों में काम करने के बाद वे कम-उत्पादकता वाले लघु उद्योगों में काम करने लगती हैं। आराम लेने या अपने बच्चों के पालन-पोषण के बाद काम की दोबारा तलाश करने वाली मझोले उम्र की महिलाओं को कौशल विकासऔर पूंजी मिल नहीं पाती है।

महिलाओं द्वारा रोजगार में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कुछ मददगार संस्थान और चलन छोटे शहरों में महिलाओं के लिये असुरक्षित नौकरियों से निपटने और पितृसत्तात्मक संरचनाओं से दूर हटने को आसान बना देते हैं। सेमारंग रेजेन्सी में प्रवासी महिलायें बोर्डिंग हाउसेज पर निर्भर रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोस्त कहा जाता है। ये साफ़-सुथरी, सस्ती और अधिकांश मामलों में काम की जगहों के नजदीक रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। औपचारिक बैंकिंग तंत्र, समूह बचतों, कर्ज लेने की योजनाओं और कुछ हद तक यूनियनों आदि व्यवस्थाओं से भी छोटे शहरों में महिलाओं को बल मिलता है।

जगह बनाना: महिलाओं का छोटे शहरों के साथ संबंध

छोटे शहरों में युवा महिलाओं की संभावनाएं कहीं न कहीं शादी से जुड़ी रहती हैं । जैसे कि शिक्षा में लम्बे समय तक बने रहकर शादी में देरी करना, या पारिवारिक उपक्रमों में या घर से काम करना । कुछ महिलायें अपने परिवारों से अन्य जगहों में अधिक प्रगतिशील परिवारों में शादी के लिये भी बातचीत करती हैं। चूंकि उनके पास सीमित अनुभव होता है, इसलिये इन युवा महिलाओं को काम के अवसर तलाशने और स्वतंत्र व्यवसायिक पहचान बनाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है।

विषय 5- छोटे शहर का नियोजन करना

क्षमता के लिए एजेंसी अनिवार्य है

भारत और इंडोनेशिया दोनों ने ही महत्वाकांक्षी विकेंद्रीकरण कार्यक्रम लागू किये हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य और प्रभाव अलग-अलग हैं। हालांकि दोनों विकेंद्रीकरण कार्यक्रमों का आरम्भ 1990 के दशक में हुआ था, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण फर्क थे। भारतीय राज्यों ने सरकार को जोड़ने और केंद्र

सरकार से मिलने वाली सहायता और आर्थिक मदद को लेने और वितरित करने वाली श्रृंखला के रूप में अपनी महत्ता बरकरार रखी। इस बीच इंडोनेशिया में शहरों और रेजेंसीज, जो सरकार का तीसरा स्तर थे, को सरकार से सीधे बड़ी मात्रा में राजकोष स्थानांतरित किया गया। नतीजतन, इंडोनेशिया के शहरी क्षेत्रों का भारतीय शहरों के मुकाबले अपने शहरी मामलों पर अधिक नियंत्रण रहा।

इंडोनेशिया में स्थानीय सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी काम, आधारभूत संरचना, सेवा, पर्यावरण, यातायात, कृषि, विनिर्माण, उद्योग और व्यापार, भूमि, श्रम और पूंजीगत निवेश जैसे अनेक प्रशासन से जुड़े कार्य सौंपे गये हैं। हालांकि मुख्य भूमिका केंद्र सरकार की ही रहती है, स्थानीय सरकारों का अपने क्षेत्रों में किये जाने वाले खर्च पर काफी अधिकार होता है। इसके विपरीत भारत में, स्थानीय समुदायों से किये गये सांविधानिक वायदे, जैसे भूमि उपयोग पर अधिकार, शहरी योजना, आर्थिक और विकास योजना आदि पूरे नहीं हो सके हैं।

बहुस्तरीय सरकारी ढांचे के भीतर नियोजन

विकेंद्रीकरण के विभिन्न मॉडलों के बावजूद भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्थानीय सरकारें अक्सर केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाले अधिसंरचनात्मक निवेश के आधार पर काम करती हुयी नजर आती हैं। उदाहरण के लिये, औद्योगिक पार्क, नया रेल फ्रेट कारिडोर, निजी क्षेत्र का लाजिस्टिक्स पार्क और नये हवाई अड्डे समेत हालिया अधिसंरचना परियोजनाओं ने किशनगढ़ को यातायात और लाजिस्टिक्स का केंद्र बना दिया है। लेकिन नगर निगम इन परियोजनाओं के नियोजन में शामिल नहीं था, न ही उसके पास इन नए कार्यों के चलते जमीन की कीमतों पर प्रभाव, घरों के लिए मांग या जनसांख्यिकीय का अनुमान लगाने की क्षमता थी। ऊपर से तय की गयीं ये प्रक्रियायें काफी दक्ष नजर आती हैं, लेकिन इन्हें स्थानीय और क्षेत्रीय कुलीन वर्ग के शक्तिशाली गुटों के प्रभाव से खतरा भी रहता है।

इसी सन्दर्भ में विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में नियोजन से जुड़े मुद्दे उठते हैं। उदाहरण के लिये, केंद्रीय जावा में, सेमारंग रेजेन्सी और पड़ोसी रेजेंसियों में निवेशकों को अपने यहाँ लाने के लिये प्रतिस्पर्धा रहती है। इस स्थिति की प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जो कि उपक्रमों के टैक्स का लाभ उठाती है। रेजेंसीज के भीतर, मुहल्लों का ग्रामीण-शहरी चरित्र नियोजन के प्रयासों को और उलझा देता है। क्योंकि स्थानीय सरकारों को ग्रामीण और शहरी विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।

आर्थिक भविष्य की परिकल्पना में संघर्ष

हालांकि भारत की तुलना में इंडोनेशिया में स्थानीय आर्थिक नियोजन अधिक ठोस है, लेकिन दोनों ही देशों में स्थानीय सरकारें टिकाऊ, समावेशी आर्थिक विकास रणनीतियां बनाने में सघर्ष करती हैं। स्थानीय सरकारों के हस्तक्षेप सामान्यतः केंद्र सरकार की योजनाओं के दिशा-निर्देशों तक सीमित हैं जिससे कौशल विकास और छोटे उपक्रमों को बढ़ाने के स्थानीय मौलिक प्रयास अवरुद्ध हो जाते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच निचले स्तर के तालमेल के चलते नौकरियों से जुड़े कार्यक्रमों में बिखराव पैदा होता है। प्रत्येक हस्तक्षेप का असर बहुत छोटा और अलग-थलग रहता है और स्थानीय श्रम बाजार पर इसका वास्तविक असर नहीं पड़ता है।

छोटे शहरों के लिये नीतिगत दिशा-निर्देश

भविष्योन्मुख अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण

1. श्रम बाजार संक्रमणों, कौशल विकास और आर्थिक प्रगति को सुगम बनाने के लिये लक्षित, स्थानीय रूप से प्रासंगिक कार्यक्रमों को बनाना।

दोनों देशों में वर्तमान में मौजूद शिक्षा और कौशल विकासनीतियां मुख्य तौर पर युवाओं को नौकरियां दिलाने पर केन्द्रित हैं। इनमें युवाओं के करियर की राह प्रशस्त करने वाली दूरदृष्टि का अभाव दिखता है। छोटे शहरों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और श्रम बाजार सूचना तंत्रों को इस तरह बनाया जाना चाहिये ताकि कामगारों को रोजगार के विभिन्न पड़ावों पर मदद मिल सके। ऐसा करते हुये, प्रवास जंक्शन के रूप में छोटे शहरों की विशिष्ट स्थिति को विभिन्न प्रकार की आबादियों की विभिन्न कौशल विकास क्षमताओं को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर विभिन्न प्रकार के कामगार और प्रवासी इन जगहों से होकर गुजरते हैं (चाहे अपनी जगहों पर जाते हुये या लौटते हुये) तो सरकारें इन जगहों पर अपने कार्यबल विकास (वर्कफोर्स डेवलपमेंट) प्रयासों का ध्यान केन्द्रित कर सकती हैं।

2. स्थानीय निजी क्षेत्र के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये उद्यमिता नीतियों को परिष्कृत करना। उद्यमिता भारत और इंडोनेशिया दोनों में इस्तेमाल होने वाली एक "क्विक फिक्स" रोजगार रणनीति है। हालांकि इससे एकल स्व-नियोजित कामगारों वाले लघु उपक्रमों के निर्माण से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। सही उद्यमिता नीति यह है कि स्थानीय जड़ों वाले निजी क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान करने और विस्तृत करने के लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। यह कार्य उन व्यवहारिक उपक्रमों के जरिये किया जाये जिनमें सार्थक स्तर पर उत्पादक नौकरियां पैदा करने की क्षमता हो।

3. सहयोगात्मक प्रशासन के जरिये ग्रामीण और शहरी इलाकों के आपसी सम्बन्ध को मजबूत करना। बहुत से छोटे शहर अपने आस-पास के गांवों से करीबी रूप से जुड़े हुये हैं और इस बात का विशिष्ट आर्थिक लाभ उन्हें मिलता है। इन ग्रामीण और शहरी इलाकों का आपसी सम्बन्ध पहले ही बेहद मजबूत हैं लेकिन उनकी ज्यादातर क्षमता का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरह छोटे शहरों और उनके आस-पास के ग्रामीण इलाकों के आपसी लाभदायक आर्थिक संबंधों से फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्थानीय सरकारों के बीच और स्वयं सरकारों में बेहतर तालमेल जरूरी है।

4. "स्टिकी", अनुकूलनीय और बढ़ावा दे सकने योग्य आर्थिक गतिविधि को अपनाना।

अपने स्थानीय श्रम बाजारों में उत्पादक रोजगार पैदा करने और प्रगति बढ़ाने के लिये छोटे शहरों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों को विकसित करना होगा जो गैर-महानगरीय जगहों में अनुकूल हों। इसके बाद उन उद्योगों को स्थानीय आर्थिक मेलजोल स्थापित करना होगा। इसके अलावा दीर्घकाल के लिये आर्थिक विकास रणनीति का निर्माण करने के लिये छोटे शहरों को किसी भी कीमत पर बाहर निवेश तलाशने के बजाय अपने साधनों-संपत्तियों का निर्माण खुद ही करना होगा।

5. ऊपर से आने वाले निवेश को सामुदायिक स्तर के नेतृत्व के साथ संयोजित करना।

हालांकि बड़े पैमाने पर होने वाले निवेश छोटे शहरों के लिये वरदान हो सकते हैं, लेकिन अगर इसे स्थानीय रूप से संचालित आर्थिक विकास और भागीदारी नियोजन से मिला दिया जाये तो इसकी रूपांतरण क्षमता काफी बढ़ सकती है। स्थानीय

नेतृत्व यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि बड़ी अधिसंरचनात्मक परियोजनायें उचित और पारदर्शी स्थानीय परामर्श के साथ पूरी हों। इसके अलावा, स्थानीय नौकरशाही, निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी में नेतृत्व का विकास कर छोटे शहर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निवेश का लाभ विभिन्न उत्पादकों को मिले।

प्रवास का प्रबंधन

1. समावेशी भूमि विनियमन और शहरी डिजाइन को लागू करना।

छोटे शहरों में संगठित-असंगठित की श्रेणियों से परे जाकर विभिन्न प्रकार की भूमियों और आवास कार्यावधि की पहचान करने का अवसर है। छोटे शहरों को सन्दर्भ का ध्यान रखकर विनियमनों को अपनाना चाहिये। इस तरह के विनियमन पारंपरिक और बहु उपयोगी मोहल्लों (मिक्सड यूज नेबरहुड) दोनों का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसे विनियमन पारंपरिक पेशों और छोटे व्यवसायों का संरक्षण करते हैं जो कि महिलाओं के काम के लिए आवश्यक है। आम तौर पर ये व्यवसाय पारिवारिक कारोबार या घर से किये जाने वाले काम हो सकते हैं।

2. प्रवासियों को शहर में आकर्षित करने और रहने के लिये सेवाओं में सुधार करना।

अगर असंगठित मोहल्लों (जिनमें बहुत से प्रवासी रहते हैं) में सेवायें उपलब्ध करायी जायें तो छोटे शहरों की प्रवासी आबादी के लिये जीवंत और सस्ते मोहल्लों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा करने के लिये, स्थानीय सरकारों को सन्दर्भ का ध्यान रखकर सबसे उचित तकनीक का चुनाव करना चाहिये-इसके लिये महानगरीय शैली वाली अधिसंरचना की हू-ब-हू नक़ल करने से बचना चाहिये और स्थानीय परिवारों की निवेश क्षमता को बढ़ाना चाहिये। इसके लिये सेवाओं में निवेश केवल कचरा प्रबंधन, पानी और साफ़-सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिये, उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंच बढ़ानी चाहिए जिनसे प्रवासी आते-जाते हैं। इसके साथ-साथ यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की देखभाल और सार्वजनिक स्थलों से जुड़े क़दमों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ानी चाहिए।

3. युवा कामगारों के लिए उचित और मजबूत किराये के आवास विकसित करना।

छोटे शहरों में आसानी से प्रवास होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि इन शहरों में किराये के आवासों को विकसित किया जाए। स्थानीय सरकारों को स्पष्ट किराया नीति बनानी चाहिये। नीति के अभाव में किराया अक्सर पारंपरिक और अनौपचारिक तरीकों से लिया जाता है जो दोनों देशों और हमारे द्वारा चयनित चारों शहरों में दिखाई पड़ता है। सामान्यतः ये पूरी व्यवस्था पूंजीवादी निवेशकों द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों द्वारा संचालित होती है। छोटे शहरों की ये किराये के बाजार अपने आप में आजीविका का साधन हैं।

4. नवाचार बढ़ाने के लिये विविधता को अपनाना।

छोटे शहरों को प्रवासियों को अपनाने के लिये स्थानीय नीतिगत ढांचे को विकसित करना चाहिये। साथ-साथ जागरूकता अभियानों के माध्यम से विविध संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली की स्वीकार्यता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल शहर प्रवासी कामगारों को बनाये रखने में मदद मिलेगी बल्कि प्रवासियों और निवासियों के आपसी सहयोग से उभरने वाले नये तरह के उपक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह, छोटे शहर बड़े महानगरीय क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले बहिष्करण के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं।

[1]Naik, M. and Randolph, G. (2018). Migration Junctions in India and Indonesia: Reimagining Places, Reorienting Policy. New Delhi: JustJobs Network & Centre for Policy Research

महिला कार्यबल की भागीदारी और आर्थिक प्रगति को तेज करना

1. महिलाओं के काम को उनके जीवन-चक्र के दृष्टिकोण से समझना ।

श्रम बल में युवा महिलाओं को बनाये रखने के लिये नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे नियोक्ता महिलाओं को नियुक्ति के समान अवसर देने के लिए जवाबदेह हो । इसके अलावा नीतियों को उन्हें महिलाओं की सुरक्षा तथा यौन शोषण से जुड़े विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर हाल में जवाबदेह बनाना चाहिए। इस संबंध में बाल-संरक्षण सेवायें भी आवश्यक हैं। इसके अलावा उद्यमिता भी अक्सर महिलाओं को श्रम बाजार में सक्रिय रहने में सक्षम बनाती है। नीतिगत ढांचों को बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण मुहैया कराने पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। इस कार्य में भारत में स्वयं-सेवी समूहों के अनुभवों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करते हुये उपक्रम सहयोग पर विशेष जोर देने की जरुरत है। महिलाओं को उद्यमियों के रूप में सफल बनाने में मदद के लिये स्थानीय सरकारों को सॉफ्ट स्किल्स, उपक्रम प्रबंधन और एकाउंटिंग में लैंगिक रूप से संवेदनशील प्रशिक्षण देना चाहिये।

2. लैंगिक रूप से समावेशी शहरी डिजाइन और प्रशासन ।

शहरी डिजाइन और मोहल्ला सुधार पर ध्यान केन्द्रित कर छोटे शहर महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी को आसान बना सकते हैं। शहर में चलने और गलियों के स्तर पर होने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले बहु उपयोगी मोहल्ले (मिक्स्ड-यूज नेबरहुड) कुल मिलाकर सुरक्षित होते हैं। अच्छे फुटपाथ, अच्छी लाइटिंग, स्ट्रीट फर्नीचर और बैठने की जगहों समेत अच्छी अधिसंरचना वाले ऐसे मोहल्लों (नेबरहुड) का संरक्षण और संवर्धन महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा अकेले बाहर जाने में सक्षम बना सकता है। इससे महिलायें केवल दिन में ही काम करने के लिए सीमित नहीं रहतीं। इससे गलियों में बातचीत भी बढ़ती है जिससे महिलाओं की सामाजिक नेटवर्कों तक पहुंच बढ़ती है। साथ-साथ श्रम बाजार से जुड़ी सूचनायें भी उन्हें ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा, उद्यमियों को युवा महिलाओं के लिये हॉस्टेल बनाने का प्रोत्साहन देने से युवा महिलाओं की उच्च शिक्षा, कौशल विकास और काम के लिये स्वतंत्र रूप से प्रवास करने की क्षमता बढ़ सकती है।